



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्रोधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 1991/चैत्र 5, 1913

No. 190] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 1991/CHAITRA 5, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(प्रौद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1991

का. प्रा. 214 (प्र)/18कक भाई डी प्रार ए/91.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग) के प्रादेश सं. 320(प्र)/18कक/भाई डी अण ए/79 तारीख 6 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रादेश कहा गया है) मैसर्स प्रोपोली जिप्पर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता नामक संपूर्ण प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 23 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी

सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, बन्द और रक्षण उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1991 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए इसे जारी रखने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। [वेस्टिंग भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. भा. 246(अ) 18/कक/आई डी आर ए/82, तारीख 25 मई, 1982]

- सं. का. भा. 832(अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 24 नवंबर, 1982
- सं. का. भा. 385(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 31 मार्च, 1983
- सं. का. भा. 872(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 30 नवंबर, 1983
- सं. का. भा. 472(अ)/18कक/आई डी आर ए/84, तारीख 28 जून, 1984
- सं. का. भा. 975(अ)/18कक/आई डी आर ए/84, तारीख 29 दिसंबर, 1984
- सं. का. भा. 275(अ)/18कक/आई डी आर ए/85, तारीख 29 मार्च, 1985
- सं. का. भा. 146(अ)/18कक/आई डी आर ए/86, तारीख 31 मार्च, 1986
- सं. का. भा. 266(अ)/18कक/आई डी आर ए/87, तारीख 30 मार्च, 1987
- सं. का. भा. 326(अ)/18कक/आई डी आर ए/88 तारीख 30 मार्च, 1988
- सं. का. भा. 247(अ)/18कक/आई डी आर ए/89, तारीख 31 मार्च, 1989 और
- सं. का. भा. 277(अ)/18कक/आई डी आर ए/90 तारीख 30 मार्च, 1990

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1992 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि में प्रभावी बना रहे।

अतः अद्य, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 क 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा ब्रह्म शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1992 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा.सं. 2(23)/80—सी. यू. एस.]

एन. धार. कृष्णन, अपर सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 26th March, 1991

S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 6th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial

undertaking known as Messers. Appollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1991, [vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)].

Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982.

S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982,

S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st March, 1983,

S.O. 372(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983,

S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,

S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985,

S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,

S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,

S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,

S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989 and

S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1992.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2), of Section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1992.

[F. No. 2(23)|80-CUS]

N. R. KRISHNAN, Addl. Secy.

